जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 08 प्रभात जालोर, बुधवार 16 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दिन भर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर ई.डी. ने कल फिर बुलाया है

इस बार राउज़ एवेन्यु कोर्ट में ई.डी. द्वारा दर्ज चार्ज शीट में सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का नाम भी जोड़ा गया है। पहले मोतीलाल वोहरा आदि का नाम भी एफआईआर में शामिल था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। गुजरात में राहुल के प्रवेश और भाजपा को गुजरात से उखाड़ फैंकने तथा कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के व्यक्त तथा घोषित किये गये उनके इरादे के बाद, गांधी परिवार के खिलाफ एक राजनैतिक तूफान खड़ा कर दिया गया है।

ईडी ने "नैशनल हैरल्ड" केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, तथा इसके साथ ही, गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को एक जमीन घोटाला केस में, ईडी ने पूछताछ के लिये तलब किया है। आज दिनभर उनसे पूछताछ की गई तथा उन्हें कल फिर बुलाया गया है।

माँ-बेटे के खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। इस चार्जशीट में सुमन दुबे तथा सैम पित्रोदा के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले, एफआईआर में मोतीलाल वोरा तथा कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल

- **अब कोर्ट, चार्ज शीट में जिनका नाम है, उनके खिलाफ आरोप पढ़कर सुनाएगा तथा मुकदमा शुरु होगा तथा दोनों तरफ के गवाहों के बयान होंगे तथा हो सकता है, गांधी परिवार के लोग (राहुल व सोनिया) केस हार जायें। फिर, इन दोनों को जेल भी भेजा जा सकता है तथा दोनों हाई कोर्ट में अपील करेंगे, यानी यह मुकदमा कई सालों तक चल सकता है।**
- **अतः, सवाल यह उठता है, इस मुकदमे का क्या मकसद है। कानून के जानकार लोगों का, जो गांधी परिवार से सहानुभूति रखते हैं, कहना है कि ई.डी. के हरकत में आने का एक ही ध्येय है, राहुल गांधी के लिये दिक्कतें बढ़ाते रहना।**

थे। अदालत अब आरोप तय करेगी, इसके बाद, ट्रायल शुरु होगा, जिसमें दोनों पक्षों के गवाह अदालत के समक्ष अपने बयान देंगे। इसके बाद , केस अपने अन्त की ओर बढ़ेगा, जिसमें गांधी परिवार को जेल की सजा हो सकती है। सजा होने की स्थिति में, गांधी परिवार को उच्चतर अदालत में जाना होगा।

इस केस पर नज़दीक से नजर रखने वाले कानूनविज्ञों का कहना है कि यह केस सालों तक खिंच सकता है।

"नैशनल हैरल्ड" केस में राहुल तथा सोनिया गांधी दोनों ही जमानत पर हैं। केस की सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। शनिवार को ईडी ने 661 करोड़ रु. की अचल सम्पत्तियाँ का कब्जा लेने के नोटिस जारी कर दिये थे।

कांग्रेस-नियंत्रित "एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनीलॉन्डरिंग के आरोपों की जाँच के सिलसिले में, ये सम्पत्तियाँ नवम्बर, 2023 में अटैच कर दी गई थीं।

ये नोटिस, जिनमें सम्बंधित परिसर खाली करने के लिये कहा गया था, दिल्ली की सम्पत्तियों, मुम्बई के बाँद्रा इलाके की सम्पत्तियों तथा लखनऊ की विश्वेश्वर रोड पर स्थित एजेएल भवन पर चस्पा कर दिये गये थे।

इन बिल्डिंगों में बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक नैशनल हैरल्ड बिल्डिंग भी शामिल है।

गांधी परिवार ने इस सब कार्यवाही पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अभिषेक सिंह तथा अन्य ने इसे राजनैतिक दुश्मनी की संज्ञा दी है।

जब 'यंग इंडियन' नामक एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक का पूर्व कांग्रेस पार्षद अजमेर में गिरफ्तार

अजमेर, 15 अप्रैल (कासं)। कर्नाटक और अजमेर जिला पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को अजमेर से कर्नाटक के कांग्रेसी नेता व पूर्व पार्षद कबीर खान को गिरफ्तार किया है। केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए गए वक्फ बिल 2025 के विरोध में कबीर खान द्वारा हिंसा भडक़ाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया था। कर्नाटक पुलिस खान को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि कर्नाटक पुलिस से सूचना मिली थी कि कांग्रेसी नेता व पूर्व पार्षद कबीर खान

- **वक्फ बिल पर हिंसा भड़काने का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने पर कर्नाटक पुलिस ने कार्यवाही की।**

अजमेर में छुपा हुआ है। जिस पर एसपी के निर्देश पर पुलिस आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थी। कर्नाटक पुलिस ने अजमेर पुलिस की मदद से आदर्श नगर थाना क्षेत्र से आरोपी कबीर खान को गिरफ्तार किया।

एसपी राणा ने बताया कि वक्फ बिल को लेकर कांग्रेसी ने खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर युवाओं को सड़कों पर उतरने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने तथा कानून के विरोध में जान की कुर्बानी देने जैसे भडक़ाऊ संदेश दिए थे। वायरल वीडियो में बसों और ट्रेनों में आग लगा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आप बोइंग कम्पनी से हवाई जहाजों की डिलिवरी लेना बंद करें'

चीन ने अपनी एयरलाइन्स को आदेश दिए

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेरिका के साथ अपने ट्रेड वॉर को और बढ़ाते हुए, चीन ने कथित तौर पर अपनी एयरलाइन्स से कहा है कि अमेरिका के एविएशन दिग्गज बोइंग से जेट विमानों की डिलीवरी लेना बंद करें। इससे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को एक स्पष्ट संकेत गया है कि बीजिंग उनके फरमानों के आगे झुकने वाला नहीं है।

जनवरी में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के बाद से, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे पर टैरिफ लगाने के युद्ध में फँसी हुई हैं, जिसमें अमेरिका अब चीन से आयात पर 145 प्रतिशत तक का शुल्क लगा रहा है।

एक मिसाल कायम करते हुए, बीज़िंग ने वॉशिंगटन की तथाकथित गैरकानूनी "दादागिरी" पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अमेरिकी आयात पर 125 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाया है।

- **चीन ने अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि चीन अमेरिका के आदेशों के आगे घुटने नहीं टेकेगा**
- **चीन ने भारत से एकदम विपरीत सोच दिखाई है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर स्थापित विश्व के वाणिज्य व व्यापार के सिस्टम के अनुसार काम करने का निर्णय लिया है।**
- **चीन ने साथ ही, अपनी एयर लाइन्स पर यह भी प्रतिबंध लगाया है कि ये कंपनियाँ अब हवाई जहाज में काम आने वाले सामान व पार्ट्स भी अमेरिका की कंपनियों से खरीदना बंद करें।**
- **चीन द्वारा अमेरिका द्वारा लगाये गये टैरिफ (125 प्रतिशत) के जवाब में उठाये गये इन कदमों से अमेरिका में निर्मित हवाई जहाज व उनके पार्ट्स खरीदना काफी महंगा सौदा हो गया है।**
- **अमेरिका ने जरुर चीन पर लगाये गये टैरिफ की सूची से चीन में निर्मित स्मार्ट फोन, सैमिकण्डक्टर्स व कम्प्यूटर्स को निकाल कर, चीन को राहत पहुँचाने की कोशिश की है।**

भारत जो दावा करता है कि वो विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, के विपरीत, चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर स्थापित विश्व के वाणिज्य व व्यापार के सिस्टम के अनुसार काम करने का निर्णय लिया है।

इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने आज

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन ने राज्य सरकारों के अधिकारों को भी चुनावी मुद्दा बनाने की ठानी

विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने, एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोज़फ, शिक्षाविद् व वाइस चांसलर के. अशोक व स्टेट प्लानिंग कमिशन के वाइस चेयरमैन एम. नागनाथन सदस्य हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। तमिलनाडु विधानसभा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और द्रमुक के चीफ एम.के. स्टालिन राज्यों की स्वायत्तता पर एक बड़ा मुद्दा उछाला है, यह आईडिया अन्य विपक्ष शासित राज्यों के लिए भी अपीलिंग है। मंगलवार को स्टालिन विधानसभा में एक बयान में उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्यों के अधिकारों का क्षरण हो रहा है और उन्हें अपने मूल अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ता है।

स्टालिन ने कहा, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने देश का राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने इसे एक राज्य नहीं बल्कि राज्यों का संघ बनाया था और संघवाद के नियमों का

- **समिति यह अध्ययन करके कि, कैसे स्टेट गवर्नमैंट के अधिकारों को कनकरंट लिस्ट में डाल कर, राज्य सरकार को कमज़ोर किया गया है और अब कैसे पुनः इन विषयों को पुनः केवल राज्य सरकार की सूची में ही "रिस्टोर" किया जाये।**
- **इस दिशा में स्टालिन ने तमिलनाडु के पूर्व मु.मंत्री करूणानिधि की 1969 में दिखाई दूर दृष्टि व हिम्मत को बधाई दी, क्योंकि वह पहला राज्य बना, जिसने राज्य व केन्द्र के अधिकारों की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश पी.वी. राजामन्नार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई थी।**

अनुसरण किया था।"

राज्य सरकारों के लिए स्वायत्तता की एक बड़ी पिच बनाते हुए उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की, जो केन्द्र व राज्य से सम्बंधित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होगी

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। देशभर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अल नीनो की स्थिति बनने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में यह

- **मौसम विभाग ने यह घोषणा की साथ ही क्लाइमेंट चेंज पर चिंता जताई व कहा कि बारिश के दिन घट रहे हैं पर भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है।**

अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश में मानसून के दौरान अच्छी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई है, जिसके तहत बारिश के दिनों की संख्या घट रही है जबकि भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खड़गे की पहल पर, आर.जे.डी. की टीम ने तेजस्वी के नेतृत्व में, कांग्रेसाध्यक्ष से मुलाकात की

छोटी-मोटी बातें, जैसे कांग्रेस को गुजरात में नहीं पटना में अधिवेशन रखना चाहिये था, तो बातचीत में निपट गईं, राहुल गांधी की उपस्थिति में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिये चुनावी रणनीति पर चर्चा करने की दिशा में पहल करते हुये, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष तेजस्वी यादव तथा मनोज कुमार झा को आमंत्रित किया।

कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यहाँ उनके निवास पर आयोजित इस मीटिंग में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल तथा आरजेडी के दोनों शीर्षस्थ नेता उपस्थित थे।

मीटिंग की जानकारी देते हुये, कांग्रेस प्रमुख ने "एक्स" पर एक पोस्ट में कहा, "आज बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ हमारी मीटिंग हुई तथा हमने "महागठबंधन" को मजबूत करने के विषय में चर्चा की।

- **पर, तेजस्वी यादव द्वारा उठाया गया मुद्दा कि कांग्रेस जमीनी स्थिति देखकर, सीटों का बंटवारा करे, पर सहमति शायद अभी नहीं बनी। तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर, केवल 19 सीटों पर विजयी हुई थी, पर, आर.जे.डी. 144 सीटों पर लड़ी थी, तथा 75 सीटें उसने जीती थीं। कांग्रेस की स्ट्राइक रेट काफी कमज़ोर है। अतः, उसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद छोड़नी चाहिये।**
- **पर, कांग्रेस इस तर्क से सहमत नहीं है तथा राहुल गांधी बिहार में बहुत अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। इसीलिये पिछले तीन माह में, तीन बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं।**
- **कांग्रेस का कहना है, नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार भी, आर.जे.डी. के जंगल राज की बात जोरों से कर रहे हैं, अतः बिहार में आर.जे.डी. की अपील सीमित है, अतः कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिये।**

कांग्रेस के कुछ वर्गों का पार्टी का यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है कि एआईसीसी अधिवेशन गुजरात में किया गया, बिहार में नहीं। दरअसल, पार्टी अधिवेशन ऐसे राज्य में ही किया जाता रहा है, जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने हों। इस संबंध में पार्टी की सोच को स्पष्ट करते हुये, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अधिवेशन का आयोजन बिहार में करने से हमारे ताकतवर मित्र दल आरजेडी तक एक गलत संकेत जाता। हम बिहार में भाजपा से आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेंगे, जबकि गुजरात में, हमें अकेले के दम पर भाजपा से लड़ना है।

बिहार के आसन्न विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुये, खड़गे ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर प्रहार करते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "इस समय, बिहार में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुर्शिदाबाद दंगा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल। वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध के बीच, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं की गई हैं। अधिवक्ता शशांक शेखर झा द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में शीर्ष अदालत की निगरानी में एक विशेष जांच

- **इन याचिकाओं में दंगा भड़काए जाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।**

दल (एसआईटी) के गठन का आग्रह किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा एक अन्य याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संबंधित घटना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगने, जान-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभी विश्व के अधिकांश देश ट्रम्प की टैरिफ यातना से स्तब्ध से खड़े है

पर, भारत, पहला देश बना, जो ट्रम्प के कंपन को लांघ कर पुनः स्टॉक एक्सचेंज में धन वर्षा की ओर बढ़ा है

-अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। मंगलवार को भारत के शेयर बाज़ार ट्रम्प टैरिफ के बाद की उथल-पुथल से उबरे और इनमें तेजी से सुधार आया। डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित अभूतपूर्व टैरिफ नीति ने वैश्विक वित्तीय बाज़ारों को हिला दिया था, जिससे कई प्रमुख वैश्विक केन्द्र अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

इसके विपरीत, भारतीय शेयरों की कीमतों में तेज वृद्धि ने भारतीय स्क्रिप के बाज़ार मूल्य में लगभग 19 लाख करोड़ रूपये जोड़े हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा टैरिफ कॉल के मद्देनज़र भारतीय इक्विटी से पूँजी की निकासी के बावजूद ऐसा हुआ है।

ट्रम्प टैरिफ की घोषणा के बाद, वैश्विक बाज़ार डूब गए थे, पर मंगलवार को भारतीय बाज़ार 2 प्रतिशत से अधिक ऊपर उठ गए। इसके विपरीत, प्रमुख वैश्विक बाज़ार अभी भी ट्रम्प के पूर्व टैरिफ स्तरों से 3 प्रतिशत से अधिक नीचे हैं। इससे भारत उथल-पुथल से पूरी तरह से उबरने वाला पहला देश बन गया है।

यह रिकवरी और भी ज्यादा उल्लेखनीय है, क्योंकि पिछले छह महीनों से शेयर बाज़ार में धीमी वृद्धि हुई है। साथ ही, अमेरिका में जो कुछ घटा, उसके बाद विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाज़ारों से पैसा निकाला है। विदेशी निवेशकों ने पिछली दो तिमाहियों में 16 बिलियन डॉलर निकाले थे और इससे स्थानीय बाज़ारों पर दबाव पड़ा था।

हालांकि, जब से ट्रम्प टैरिफ की घोषणा की गई है, भारत में एक अलग स्थिति सामने आई है। शुरुआत में बाज़ार गिर गए थे, लेकिन यह जल्दी से ठीक हो गए, क्योंकि यह महसूस किया गया कि अमेरिका के प्रति भारत का "एक्सपोज़र" न्यूनतम था और विश्व के अन्य देशों में क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन इस पर अत्यधिक निर्भर नहीं था।

- **गत मंगलवार को भारत के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की कीमत में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई, उन दिनों की तुलना में जब ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी। जबकि विश्व में अन्य देशों में अभी 3 प्रतिशत की गिरावट है, शेयर वैल्यूज़ में।**
- **इस अद्भुत अनुभव का कारण है, भारत का उद्योग अपनी "डॉमैस्टिक डिमांड" पर निर्भर है तथा अमेरिका का एक्सपोज़र काफी कम है।**
- **दूसरी ओर भारत ने अमेरिका को चुनौती देने के बजाय, मिल बैठकर बातचीत करने की नीति अपनाई।**
- **चीन ने डब्ल्यु.टी.ओ. का भरपूर लाभ उठाया, छोटे-विकासशील देशों को "दबाकर", अब, यह छवि चीन के खिलाफ भारी पड़ रही है। एक बार तो चीन का आर्थिक आधिपत्य इतना था कि उसे विश्व की फैक्टरी कहा जाने लगा था।**
- **पर, अगर भारत को इस अवसर का लाभ लेना है तो उद्योगों व माइन्स के लिये भूमि उपलब्ध कराने में जो भी रोड़े हैं, उन्हें हटाना होगा, साथ ही आज की परिस्थिति के अनुसार, "लेबर लॉज़" में उचित परिवर्तन करना होगा।**

सामान्य पतन के दृश्य के बीच, भारत के बाज़ार अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत पर ठीक हो गए हैं। घरेलू माँग मजबूत है और भारतीय कंपनियाँ देश भर के उपभोक्ताओं से बढ़ती माँग का लाभ उठाने की उम्मीद करती हैं।

मौलिक रूप से, निवेशक घरेलू बाज़ार और ट्रम्प के लगाए टैरिफ से निपटने में भारत के रुख पर भरोसा कर रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ से सीधे टकराने की बजाय भारत ने सुलह का रुख अपनाया है और अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम करने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरु

श्रीनगर, 15 अप्रैल। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु देश भर की 533 बैंक शाखाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और हैल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इस बार श्रद्धालु पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और

- **यात्रा 3 जुलाई से शुरु हो रही है तथा 13 से 70 साल के लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।**

कश्मीर बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में भी 20 शाखाएं हैं जहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन शुल्क 150 रुपये है तथा 13 से 70 साल तक के लोग ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्रद्धालु पहलगाम या बालटाल में से किसी भी रास्ते से यात्रा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK CMYK